

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, सोमवार, शके 1941-जनवरी 6, 2020 Pausa 16, Monday, Saka 1941-January 6, 2020	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात) विभाग

आज्ञा

जयपुर, नवम्बर 28, 2019

संख्या प३(१) वित्त/एफआरबीएम/एफसी एण्ड ईएडी/२०१५ : राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, २००५ की धारा ८

के तहत लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति का एतद्वारा पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

१-	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	-	पदेन अध्यक्ष
२-	श्री सुनील धारीवाल, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)	-	अशासकीय सदस्य
३-	श्री एस.के.मिस्तल, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)	-	अशासकीय सदस्य
४-	प्रो. एन.डी.माथुर, अर्थशास्त्री	-	अशासकीय सदस्य
५-	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त	-	पदेन सदस्य

शासन सचिव वित्त (बजट) गैर-सदस्य सचिव होंगे तथा वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन, वित्त विभाग, समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।

समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :-

- (१) विभिन्न विभागों के लिये कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों और स्कीमों का समान विभागों और अन्य विभागों के भीतर कार्यक्रमों और स्कीमों की तुलना में उपयोगिता और उनके तुलनात्मक फायदों का निर्धारण करने के दृष्टिकोण से पुनर्विलोकन करना;
- (२) परिव्ययों के प्रति व्यय की सीमा का पुनर्विलोकन करना और ऐसी प्रणाली और तंत्र की गुणवत्ता का निर्धारण करना जो ऐसे व्यय को नियंत्रित और पुनर्विलोकित करे;
- (३) उपर्युक्त के परिणाम के रूप में, स्कीमों के या उनकी अन्तर्वस्तु के चयन में मध्यमकालिक शुद्धिकरण या दीर्घकालिक परिवर्तनों के लिये सुझाव देना और अन्तरविभागीय या अन्तरस्कीम आवंटनों का पुनर्विलोकन करना;
- (४) स्कीमों/ कार्यक्रमों के परिणामों के बेहतर मूल्यांकन और सेवा परिदान में सुधार करने के लिये अर्थोपाय का सुझाव देना;
- (५) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और राज्य सरकार के मध्यमकालिक राजवित्तीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करना;
- (६) समस्त सहायकियों, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों, के ढांचों को पुनर्विलोकन करना, उनको बनाये रखने के लिये मूलाधार की परीक्षा करना और सहायकियों को पारदर्शी बनाने के लिये सिफारिशें करना और लक्षित जनसंख्या पर उनके प्रभाव को न्यूनतम लागत पर अधिकतम करने के लिये उपाय सुझाना;
- (७) विभागीय और वाणिज्यिक इकाइयों के उपयोक्ता प्रभारों के अवधारणा के लिये ढांचे का पुनर्विलोकन करना और उपयोक्ता प्रभारों के माध्यम से लागत वसूली के लिये प्रभावी युक्ति का सुझाव देना;
- (८) राज्य सरकार, संबद्ध कार्यालयों और संस्थाओं के अधीन कर्मचारिवृन्द व्यवस्था की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन करना और विभिन्न सेवाओं में कर्मचारियों और संवर्गों को युक्तिसंगत बनाने के लिये उपाय सुझाना। इस संदर्भ में अधिशेष कर्मचारिवृन्द की पुनः तैनाती और पुनः प्रशिक्षण की विद्यमान व्यवस्थाओं का यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्विलोकन भी करना कि राज्य सरकार के क्रियाकलापों के नये क्षेत्रों के लिये किसी अतिरिक्त जनशक्ति की पूर्ति पुनः तैनाती से हो जाये;

(९) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया और उनके वित्तपोषण के पैटर्न का पुनर्विलोकन करना और उनके क्रियाकलापों में सुधार करने और बजटीय समर्थन कम करने के लिये उपायों का सुझाव देना; और

(१०) राज्य सरकार के व्यय प्रबंधन संबंधी किसी अन्य सुसंगत विषय पर विचार करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

समिति के गैर सरकारी सदस्यों की सेवा शर्तें राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, २००६ के नियम ७ के अनुसार होंगी।

आज्ञा से,

निरंजन आर्य,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।

Finance (FC & EAD) Department
ORDER
Jaipur, November 28, 2019

No.F.3(1)/FD/FRBM/FC&EAD/2015 .-Public Expenditure Review Committee is hereby reconstituted under Section 8 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 as follows :-

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Chief Secretary, Government of Rajasthan | - Ex-officio Chairperson |
| 2. | Shri Sunil Dhariwal, Retd. IAS | - Non- official Member |
| 3. | Shri S.K. Mittal, Retd. IAS | -Non- official Member |
| 4. | Prof. N.D. Mathur, Economist | -Non- official Member |
| 5. | Addl. Chief Secretary, Finance | - Ex-officio Member |

Secretary Finance (Budget) will be the non-member Secretary of the Committee and Finance Commission & Economic Affairs Division, Finance Department, will be the administrative department for the Committee.

The terms of reference of the Committee shall be as follows:-

- (i). to review the programmes and schemes being implemented for various departments, from the point of view of utility and assessing their comparative benefits vis-à-vis, the programmes and the schemes within the same departments and other departments.
- (ii). to review the extent of expenditure against outlays and to assess the quality of systems and mechanism that control and review such expenditure.
- (iii). to suggest, as a consequence of the above, mid term corrections or long term changes in the selection of the schemes, or their contents, and review inter-departmental or inter-scheme allocations.
- (iv). to suggest ways and means for better evaluation of the outcome of the schemes/programmes, and improving service delivery.
- (v). to review the implementation of the various provisions of Act and the Medium Term Fiscal Programme of the State Government.
- (vi). to review the framework of all subsidies, both explicit and implicit, examine the economic rationale for their continuance and make recommendations for making subsidies transparent and suggest measures for maximising their impact on the target population at minimum cost.
- (vii). to review the framework for determination of user charges of departmental and commercial entities and suggest an effective strategy for cost recovery through user charges.

- (viii) to review the adequacy of staffing under the State Government, attached offices and institutions and suggest measures for rationalising the staff and cadres of different services. In this context also review the existing arrangements for re-deployment and re-training of surplus staff to ensure that any additional manpower for new areas of Government activities are met by re-deployment.
- (ix). to review the procedure for setting up of Government funded autonomous institutions and their pattern of funding and suggest measures for effecting improvement and reducing budgetary support for their activities.
- (x). to consider any other relevant issue concerning expenditure management in State Government and make suitable recommendations.

The terms and conditions of the services of non-official members of the Committee will be as prescribed under Rule 7 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006.

By order
Niranjan Arya,
Addl. Chief Secretary, Finance.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।